

III  
समझ : श्रीमान कैलाल गोप्तवा महोदय, जबलपुर मध्य प्रदेश  
पुनरीकाण क्रमांक : 4355/2018/जबलपुर/भ्रा.

आवेदकगण : 1- अशोककुमार नवलरमानी उमे 55 वर्ष  
रिवीजनकर्तगण : पिता - श्री हरदासमल नवलरमानी  
2- श्रीमति आशा नवलरमानी उमे 53 वर्ष  
पति - श्री अशोककुमार नवलरमानी  
दोनों निवासी - 1256 विजयनगर विवेकानन्द  
वार्ड, जबलपुर मध्य प्रदेश

#### विरुद्ध

अनावेदक

: मध्य प्रदेश शासन व्यारा  
तहसीलदार गोरखपुर वृत्त - 2 जबलपुर

आवेदन प्राप्त  
Rahim  
22-6-18

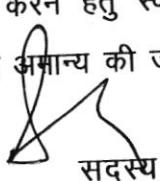
कृपया अवश्य अभिवक्तव्य सारा प्रदर्शन  
करना।

आवेदकगण निम्न विनाय करते हैं कि :-

- 1- यह कि, आवेदकगण की व्यवसायिक उपयोग की दुकान मौजा पोलीपाठी नंबर 0-167 पटोडोडो-24/2 न्या 29 वर्तमान में पोडोनं 08, रोड नं 0 में जबलपुर - 1 घारीघाट वार्ड नर्मदानगर में स्थित भूमि खसरा नंबर 24/2 के भाग जो किनारांतरण पश्चात खसरा नंबर 24/2 में निर्मित 384 वर्गफुट ₹ 24x16 की दुकान जिसका नगर निगम मकान नं. 1227 घ 3 नर्मदानगर घारीघाटवार्ड जबलपुर है जिसे संलग्न बैनामा दिनांक - 18/2/14 व उसके नलों में छौदृढ़दी सहित दर्शाया गया है जिसमें आवेदकगण नर्मदा बैंकरी के नाम से प्रतिष्ठान घलारहे हैं जिसे आगे वाद्यग्रस्त करकर संबोधित किया जायेगा।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
भाग—अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी—4355/2018/जबलपुर/भू.रा.

रथान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-08-18	<p>यह निगरानी तहसीलदार गोरखपुर-2 जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 3/अ-70/15-16 में पारित आदेश दिनांक 30-4-2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>3/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के साथ प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि तहसीलदार गोरखपुर -2 जबलपुर द्वारा आदेश दिनांक 30-4-2016 के अंत में इस प्रकार निर्णय लिया है :—</p> <p>“ अतः म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत मौजा पोलीपाथर के ख. नं. 24/2 के रकबा 0.239 है. का अंश रकबा 384 वर्गफुट से अनावेदक अशोक नवलानी पिता हरदासमल नवलानी को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। यह भी आदेशित किया जाता है कि उक्त रकबा से अपना निर्माण एंव निर्माण सामग्री 7 दिवस के अंदर हटा लें। अन्यथा उक्त निर्माण को हटाने का जो भी खर्च आयेगा वह भू राजस्व के बकाया की भौति अनावेदक से वसूल किया जायेगा। ”</p> <p>स्पष्ट है कि तहसीलदार का आदेश अंतरिम आदेश न होकर म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत अंतिम आदेश है जो संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील योग्य है।</p> <p>म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को—आपरेटिव सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरुद्ध बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सबसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।</p> <p>आवेदकगण सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। तदनुसार निगरानी प्रचलन—योग्य न पाने से इसी—स्तर पर अमान्य की जाती है।</p>  <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	